सत्यमेव जयते
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF
INFORMATION AND BROADCASTING

गगनचुंबी सफलताओं की ओर

नए भारत की महिलाएं

विषय सूची

प्रस्तावना

1. बालिका का महत्व 1
2. शिक्षा समर्थ बनाती है 13
3. सामाजिक समावेशन और गतिशीलता 25
4. सुरक्षा और रक्षा 39
5. # भारत की लक्ष्मी 51
6. स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती 61
7. 5 ट्रिलियन डॉलर तक की यात्रा में अग्रणी महिला 79
8. #SheInspiresUs 95

परिचय

लाल किले की प्राचीर से, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने पहले संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिया कि भारतीय महिलाओं के लिए एक नये युग की शुरुआत होने वाली है।

बेटी बचाओ के भावपूर्ण आह्वान से लेकर समाज से इस मौलिक सवाल तक कि वह चुनिंदा तरीके से महिलाओं के मुद्दे पर क्यों कतराता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महिलाओं को सशक्त बनाने की संकल्पना का समाज के सभी वर्गों के लोगों ने स्वागत किया।

तब से, महिलाओं के लिए तेजी से और उपयुक्त माहौल बनाया गया है, ताकि वे अपने विकल्प चुन सकें और उन विकल्पों को बिना किसी बाधा के मुकाम तक पहुंचा सकें।

उद्यमिता हो अथवा शिक्षा, खेल-कूद अथवा स्टार्टअप, रक्षा अथवा सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा अधिकार प्रत्येक क्षेत्र में जबर्दस्त सुधारों की पहल की गई है, ताकि नये भारत की महिलाओं के लिए रास्ता साफ किया जा सके।

देश की संकल्पना और कार्यों में तब्दीली की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं को भारत के विकास का लाभ मिले और इन सबसे ऊपर भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आगे आएं।

जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं कहा कि यह महिला विकास का युग नहीं है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास का युग है।

मैरी कॉम

एम.सी मैरी कॉम भारत की दिग्गज बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। वह अभूतपूर्व तरीके से सभी बाधाओं को पार करते हुए उम्मीद की किरण के रूप में उभरी। मणिपुर की रहने वाली मैरी कॉम ने शुरुआत में अपने माता-पिता के विरोध के बावजूद बॉक्सिंग को खेल के रूप में अपनाया।। मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र महिला हैं, जो रिकॉर्ड 6 बार विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बन चुकी हैं और वह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न प्राप्त कर चुकी हैं। साथ ही उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है।

मैरी कॉम की दृढ़ता ने न केवल उनके धुर विरोधियों को पराजित किया बल्कि युवा लड़कियों की पीढ़ी को खेलों में दिलचस्पी लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

1 बालिका का महत्व

किसी भी बालिका का संघर्ष दुनिया में कदम रखने से पहले ही शुरू हो जाता है। कुछ मामलों में उसे जन्म लेने की भी इजाजत नहीं मिलती। यह एक सामाजिक बुराई है, जिसे दूर किये जाने की आवश्यकता है।

लेकिन ऐसा करने के लिए एक विश्वसनीय चेहरे और मर्मस्पर्शी संदेश की आवश्यकता है। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया, एक विश्वसनीय नेता और आह्वान एक साथ किया गया तथा लोगों ने अपने दिलों में इस बात को बसा लिया। इसका नतीजा सभी के सामने है।

बेटी बचाओ, उसे शिक्षित बनाना और वित्तीय दृष्टि से उसका भविष्य सुरक्षित करना नये भारत में महिला को सशक्त बनाने का मूल सिद्धांत है।

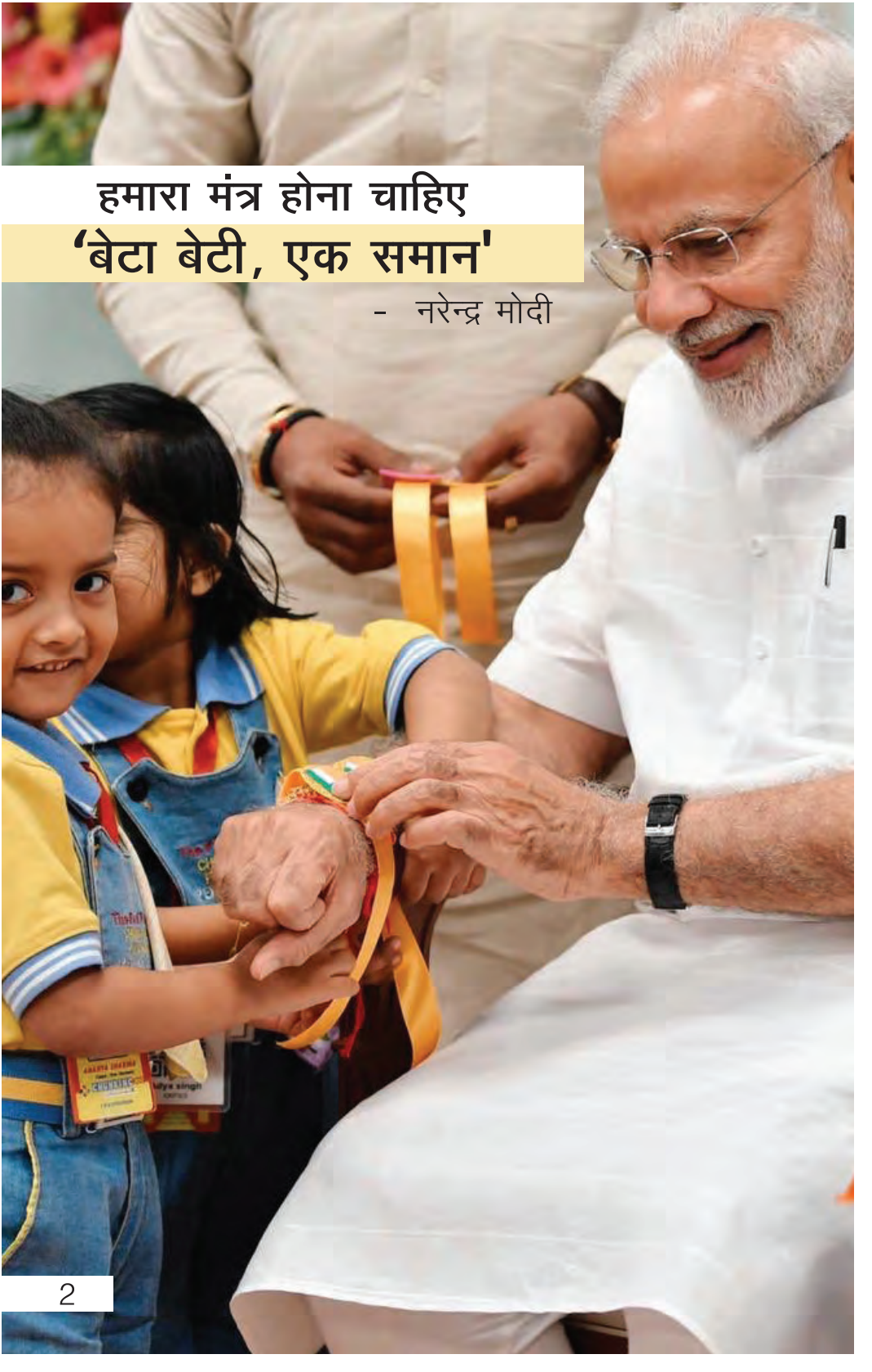

हमारा मंत्र होना चाहिए
‘बेटा बेटी, एक समान'

\- नरेन्द्र मोदी

लिंग अनुपात

बेटियों के जन्म के स्वागत के साथ भारत में लिंग अनुपात में सुधार

वर्ष 2015 में बेटियों को बचाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की पहल से एक जबर्दस्त बदलाव आया।

भारत के शहरी इलाकों में लिंग अनुपात में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2011-12 में लड़कों की तुलना में लड़कियों का लिंग अनुपात 922 था, जो 2017-18 में बढ़कर 965 हो गया।

प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बालिकाओं के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिली।

शिक्षा के सैकेंडरी और उच्च स्तरों में भी महिलाओं की भागीदारी में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिली।

भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की हिस्सेदारी

ग्रामीण

	निरक्षर	प्राइमरी तक	मिडिल सैकेंडरी	और ऊपर
2011-12	47.5	21.3	13.8	17.4
2017-18	41.8	17.7	17.8	22.7

शहरी

	निरक्षर	प्राइमरी तक	मिडिल सैकेंडरी	और ऊपर
2011-12	22.6	17	15.1	45.3
2017-18	20.8	14.5	18.3	46.4

भारत के 104 जिलों में जन्म के समय लड़कियों का लिंग अनुपात बढ़ने की जानकारी मिली, जबकि 119 जिलों में गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में पंजीकरण की दिशा में प्रगति संबंधी जानकारी मिली।

संस्थागत डिलीवरी में 146 जिलों में सुधार देखने को मिला।

इससे पूर्व, हरियाणा को लिंग अनुपात में जटिलता के कारण बाहर रखा जाता था, लेकिन अब इस राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात में प्रभावशाली वृद्धि देखने को मिली, जो 2014-15 में 871 थी वह 2018-19 में बढ़कर 923 हो गई।

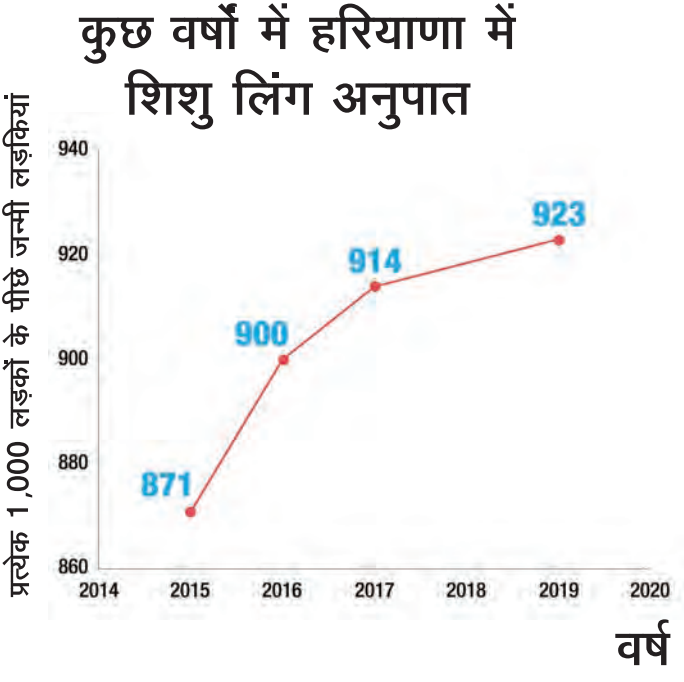

नवोन्मेषी आंदोलनों के जरिए
बदलती मानसिकता

#बेटी के साथ सेल्फी, हरियाणा के एक सरपंच के सोशल मीडिया ट्रेंड, जिसको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रोत्साहित किया, वह विश्वव्यापी शीर्ष ट्रेंड बन गया।

#मेरी बेटी मेरा गर्व, सोशल मीडिया का 2020 में एक हिट ट्रेंड, बेटियों के प्रति खुशी और गर्व जाहिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में शुरू किये गये भारत की लक्ष्मी अभियान को सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए चलाया गया।

> “किसने कल्पना की थी कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान न केवल देश भर में फैलेगा, बल्कि अन्य देशों में भी फैल जाएगा।”
>
> - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मैं समझती हूं यह बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा अभियान चल रहा है, जिसमें शिक्षा तक और अधिक लड़कियों की पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मैं समझती हूं कि यह आश्चर्यजनक है कि नीतिगत महत्व के रूप में इस पर जोर दिया जा रहा है। हमेशा कोई न कोई मुद्दा कार्यान्वयन के लिए रहता है, इसलिए मैं समझती हूं कि इरादे बहुत अच्छे हैं और इसे तेजी से कार्यान्वित होते हुए देखना अदभुत है।

अनीता भाटिया
कार्यकारी उप निदेशक
संसाधन प्रबंधन, निरंतरता और
साझेदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र में
सहायक महासचिव

सुकन्या समृद्धि योजना

बालिकाओं के लिए एक खाता

सुकन्या समृद्धि खाते छोटे बचत खाते हैं, जहां माता-पिता अपनी बेटी के नाम से धनराशि जमा कर सकते हैं।

यह खाता आकर्षक ब्याज दर सुनिश्चित करता है, भविष्य में लड़की की शिक्षा अथवा विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करता है।

जनवरी, 2020 तक 1.52 करोड़ खाते खुल चुके थे, जिनमें 46,549 करोड़ रुपये जमा किये जा चुके थे, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है।

सरकार ने बचत में उच्च ब्याज दर प्रदान कर इन खातों को प्रोत्साहित किया। बदले में सुनिश्चित किया गया कि माता-पिता को धनराशि जमा होने के लाभ दिखाई देते रहें।

हिमाचल प्रदेश

"आज मेरी कक्षा में 11 लड़कियां हैं... इस वर्ष 8वीं कक्षा की 15 लड़कियां हैं। मेरी अनेक मित्र अगले सत्र में स्कूल में शामिल होंगी"

रीना कुमार
रेहना सरकारी स्कूल, हरियाणा

"मैं शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर से पैदल चलती थी, जो कॉलेज से दो किलोमीटर दूर था। हालांकि, यह ऐसी कठिन स्थिति थी, लेकिन मैंने किसी तरह काम चलाया, यह भारत में स्वच्छता के मामले में आंखें खोल देने वाली स्थिति थी।"

- **सुधा मूर्ति**
अध्यक्ष इंफोसिस फाउंडेशन

लड़कियों के लिए
स्कूल में शौचालय

मूलभूत स्वच्छता के अभाव के कारण लड़कियों के बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने की दर काफी अधिक थी। उस समय शिक्षा के लिए स्कूलों में नाम लिखने के लिए लड़कियों को हतोत्साहित किया जाता था।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 2014 में दिए गए अपने पहले भाषण में की गई घोषणा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उद्देश्य प्रत्येक सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय का निर्माण करना था।

एक वर्ष के भीतर स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत लड़कियों के लिए 4.17 लाख अलग शौचालयों का निर्माण किया गया ।

लल्लेश्वरी

लाल देध, के नाम से मशहूर, लल्लेश्वरी कश्मीर की शैव परम्परा की एक प्रमुख महिला संत थीं। उन्होंने अपनी भाषा कश्मीरी साहित्य में जबर्दस्त योगदान दिया। 'वक्श' नाम की उनकी कविताएं कश्मीर क्षेत्र की धार्मिक परम्परा का स्रोत बनीं। उन्होंने मातृभाषा में लिखा, अतः आम आदमी के लिए समृद्ध ज्ञान के द्वार खुले।

लल्लेश्वरी उन संभावनाओं का प्रतीक है कि ज्ञान के लिए एक महिला की पहल उसके लिए और उस समाज के लिए रास्ता खोल सकती है, जिसका वह हिस्सा है।

2 शिक्षा-सशक्तिकरण का माध्यम

प्राचीन भारत में भी गार्गी, मैत्रेयी, उभयभारती जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त और स्पष्टवादी महिलाओं का इतिहास रहा है। शिक्षा, अधिकारिता का सबसे पारंगत और अपरिवर्तनीय रूप है।

शिक्षा एक महिला में उसकी क्षमताओं में आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यह एक महिला की सृजनात्मक क्षमता में निपुणता की बढोत्तरी कर व्यवसायिक कौशल में बदलाव को सुनिश्चित करती है। शिक्षा बेहतर और चुने हुए निर्णय लेने का माध्यम भी बनती है।

महिलाओं के लिए माध्यमिक और उच्चतम शिक्षा की पहुंच में सुधार सरकार के लिए दशकों तक चुनौती थी। शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों और प्रभाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ बेटी बचाओ पर जोर दिया बल्कि बेटी बढ़ाओ पर भी ध्यान केंद्रित किया।

लड़कियों और लड़कों का सकल प्रवेश अनुपात (प्रतिशत में)

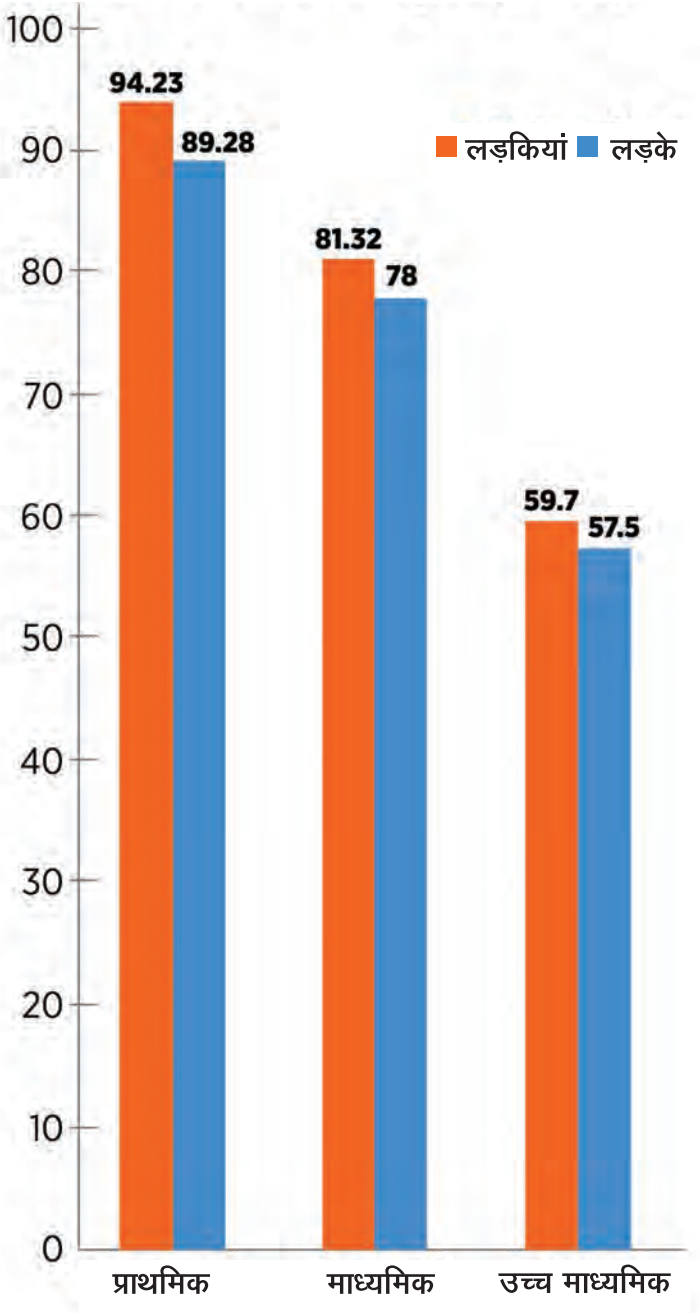

*स्रोत – बजट भाषण, वित्तीय वर्ष 2020-21

बेटी पढ़ाओ

अभियान की अभूतपूर्व सफलता

सभी स्तरों पर स्कूलों में प्रवेश करने वाली लड़कियों का अनुपात लड़कों से अधिक हुआ ।

प्राथमिक स्तर पर 89.29 प्रतिशत लड़कों के अनुपात में प्रवेश करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 94.32 हुआ ।

माध्यमिक स्तर पर 78 प्रतिशत लड़कों के अनुपात में प्रवेश करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बढ़कर 81.32 प्रतिशत हुआ ।

उच्च माध्यमिक स्तर पर भी 57.54 प्रतिशत लड़कों के मुकाबले में लड़कियों का अनुपात बढ़कर 59.70 प्रतिशत हुआ ।

बालिकाओं की प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में सुविधा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 12वीं कक्षा तक अध्ययन की व्यवस्था की गई।

दिसंबर 2019 तक

4,881

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में

6.18 लाख

लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ये सभी छात्राएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग की हैं। ये छात्राएं सरकार द्वारा अंत्योदय के लक्ष्य को दर्शाती हैं।

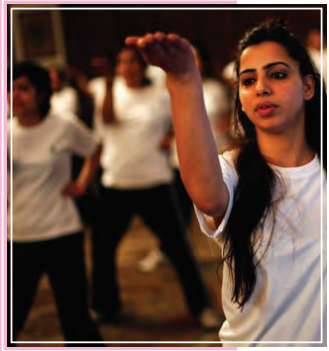

सभी लड़कियों के लिए

आत्मरक्षा को सुनिश्चित करना

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में छठी से बारहवीं तक की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सिर्फ वर्ष 2019-20 में ही 1.8 लाख प्राथमिक और 81,800 माध्यमिक स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए 220 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत

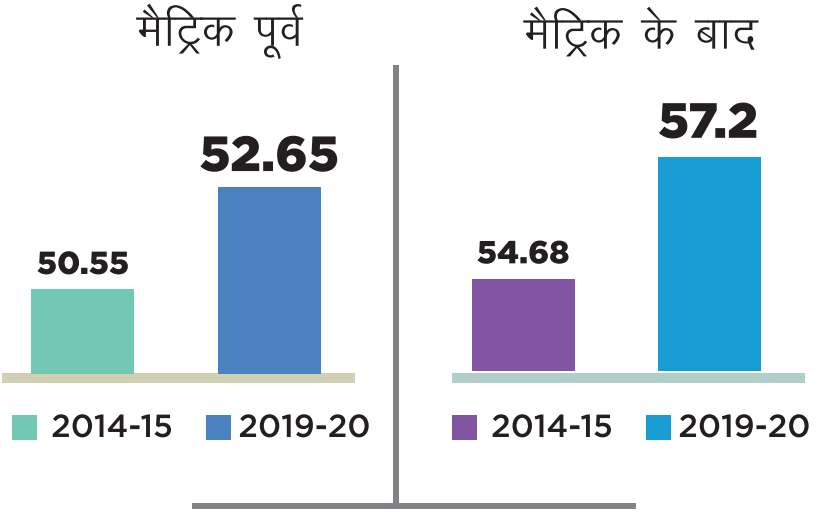

योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत

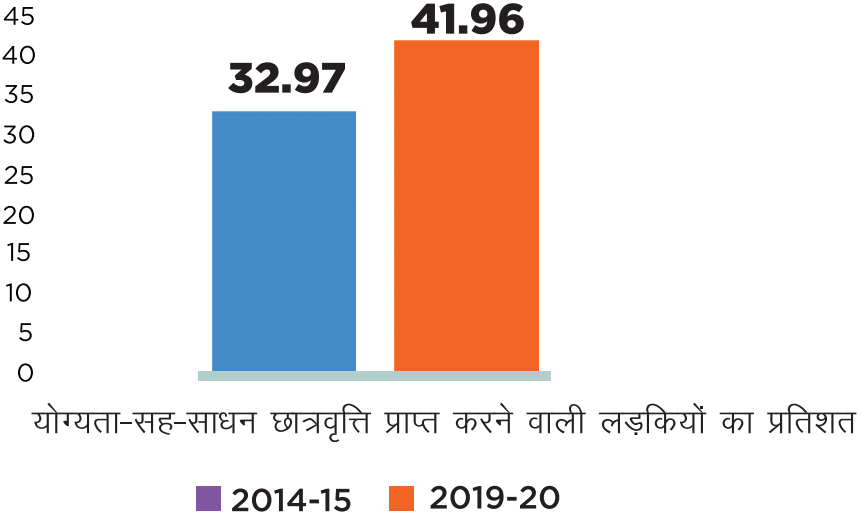

बेटी पढ़ाओ

को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर

छात्रवृत्ति का प्रावधान

पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों को प्रति माह 200 रुपये का वजीफा ।

सीबीएसई विद्यालयो में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली प्रत्येक मेधावी इकलौती छात्रा को प्रतिमाह 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि ।

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 4 हजार "बालिका छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति"योजना ।

कॉलेज और विश्वविद्यालय में केंद्रीय क्षेत्र योजना छात्रवृत्ति के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मेधावी बालिका छात्राओं के लिए प्रत्येक वर्ष 41 हजार छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है।

लड़कियों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष 3 हजार रुपये की गई ।

बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर छात्रवृत्ति का प्रावधान

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 14 से 18 आयु वर्ग में बालिकाओं के प्रवेश को बढ़ावा दिया जाता है।

वर्ष 2014 से दिसंबर 2019 तक 19.72 लाख से अधिक लड़कियों को 591.88 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।

वर्ष 2017 से 2020 के मध्य अल्पसंख्यक समुदाय की 1.53 करोड़ छात्राओं के आवेदनों को मंजूरी दी गई और 2,315 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।

आईआईटी में प्रत्येक वर्ष दाखिला लेने में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई

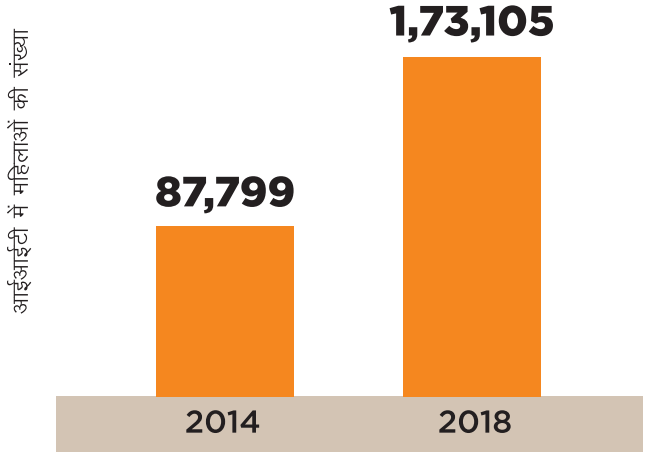

महिलाओं के कौशल में वृद्धि कर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना

वर्ष 2016 से 2020 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत 26.75 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया

वर्ष 2014 के मुकाबले 2018 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों(आईटीआई) में सालाना नामांकन में 97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

पूर्व अध्ययन की पहचान (आरपीएल) के अंतर्गत 4 लाख से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया। इससे उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हुए।

33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में से 18 संस्थान महिलाओं के लिए स्थापित किए गए हैं।

लड़कियों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष 3 हजार रुपये की गई ।

भारत की प्रमुख महिला वैज्ञानिक

डॉ. अर्चना शर्मा
इंजीनियर

डॉ. अन्ना मर्णि
मौसम वैज्ञानिक

डॉ. जानकी एमल
वनस्पति शास्त्री

डॉ. दर्शन रंगनाथन
कार्बनिक रसायन शास्त्री

डॉ. राजेश्वरी चटर्जी
इंजीनियर

डॉ. आसिमा चटर्जी
रसायन शास्त्री

डॉ. कादंबिनी गांगुली
डॉक्टर

डॉ. बिभा चौधरी
भौतिक विज्ञानी

डॉ. इरावती कर्वे
मानव विज्ञानी

डॉ. कमल रानादिव
औषधि

डॉ. रमन परिमला
गणितज्ञ

अनुसंधान को प्रोत्साहन

विशिष्ट महिलाओं का सम्मान

लड़कियों को अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट महिलाओं के नाम पर 11 आचार्य पद की स्थापना करेगा।

इन आचार्य पदों की स्थापना प्रतिष्ठित महिला वैज्ञानिकों डॉ. इरावती कर्वे,डॉ. कादंबिनी गांगुली और डॉ. अन्ना मणि आदि के नाम पर की जाएगी

इससे साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भी समाज शास्त्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालयो में विशिष्ट महिलाओं के नाम पर 10 आचार्य पद की स्थापना करेगा।

ये दस आचार्य पद प्रतिष्ठित महिला प्रशासकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और सामजिक सुधारकों जैसे अहिल्याबाई होल्कर,आनंदीबाई जोशी और रानी गाइदिनल्यू आदि के नाम पर स्थापित किए जाएगें।

प्रत्येक आचार्य पद के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

रानी गाइदिनल्यू

रानी मां के रूप में याद की जाने वाली रानी गाईदिनल्यू मणिपुर की भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रेरणादायक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की थी।

रानी गाइदिनल्यू ने न सिर्फ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी बल्कि उन्होंने गांधीजी के शांति,अहिंसा और पूर्वोत्तर भारत में भारत की एकता और अखंडता के संदेश का प्रसार किया। 14 वर्ष कारावास में बिताने के बाद उन्हें 1947 में रिहा गया गया। रानी गाईदिनल्यू ने लोगों के उत्थान के लिए शांतिपूर्ण,लोकतांत्रिक और अहिंसावादी रूप से कार्य किया।

रानी गाईदिनल्यू किसी भी प्रकार के अन्याय से लड़ने के लिए आत्मविश्वास की अद्भुत शक्ति का प्रतीक थीं।

3 सामाजिक समावेशन और गतिशीलता

भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाना मोदी सरकार का मुख्य ध्येय है। इस उद्देश्य की पूर्ति करना सामाजिक सशक्तिकरण की कुंजी है। सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिससे महिलाएं तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों की जंजीरों से मुक्त हुई हैं।

सेना, नौसेना एवं वायुसेना जैसे वर्दीधारी बलों में महिलाओं के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इससे उन बालिकाओं के लिए नए आदर्शों का सृजन होता है, जिनकी आंखों में सपने हैं तथा जो अगली पीढ़ी को प्रभावित करते हैं।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A जैसे भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाकर, एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना की गई है, जहां महिलाओं के लिए संपत्ति संबंधी अधिकारों से इनकार करना अब अतीत की बात हैं।

नए भारत में, महिलाएं राजनीति एवं खेल से लेकर न्यायपालिका और व्यापार तक प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं।

तीन तलाक की समाप्ति से महिला सशक्तिकरण में योगदान होगा तथा हमारे समाज में महिलाओं को सम्मान मिलेगा, जिसकी वे हकदार हैं।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अन्यायपूर्ण तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं मुक्ति मिली

मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक को खत्म करने के उद्देश्य से कई दशकों से संघर्ष किया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला पलट दिया गया, किन्तु इन महिलाओं को न्याय नहीं दिया गया। कई दशकों तक संघर्ष के बाद, ऐतिहासिक मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को संसद में पारित किया गया, जिसने तत्काल तीन तलाक को एक अपराध घोषित कर दिया, जिसके लिए तीन वर्ष तक कैद की सजा निर्धारित की गई। इससे मुस्लिम महिलाओं का सदियों से चला आ रहा शोषण तथा असमानता के व्यवहार का अंत हुआ।

मोदी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष साथी के हज यात्रा पर जा सकती हैं। इससे मुस्लिम महिलाओं के बीच काफी खुशी आई, क्योंकि अब अकेली मुस्लिम महिला भी हज यात्रा पर जा सकती है।

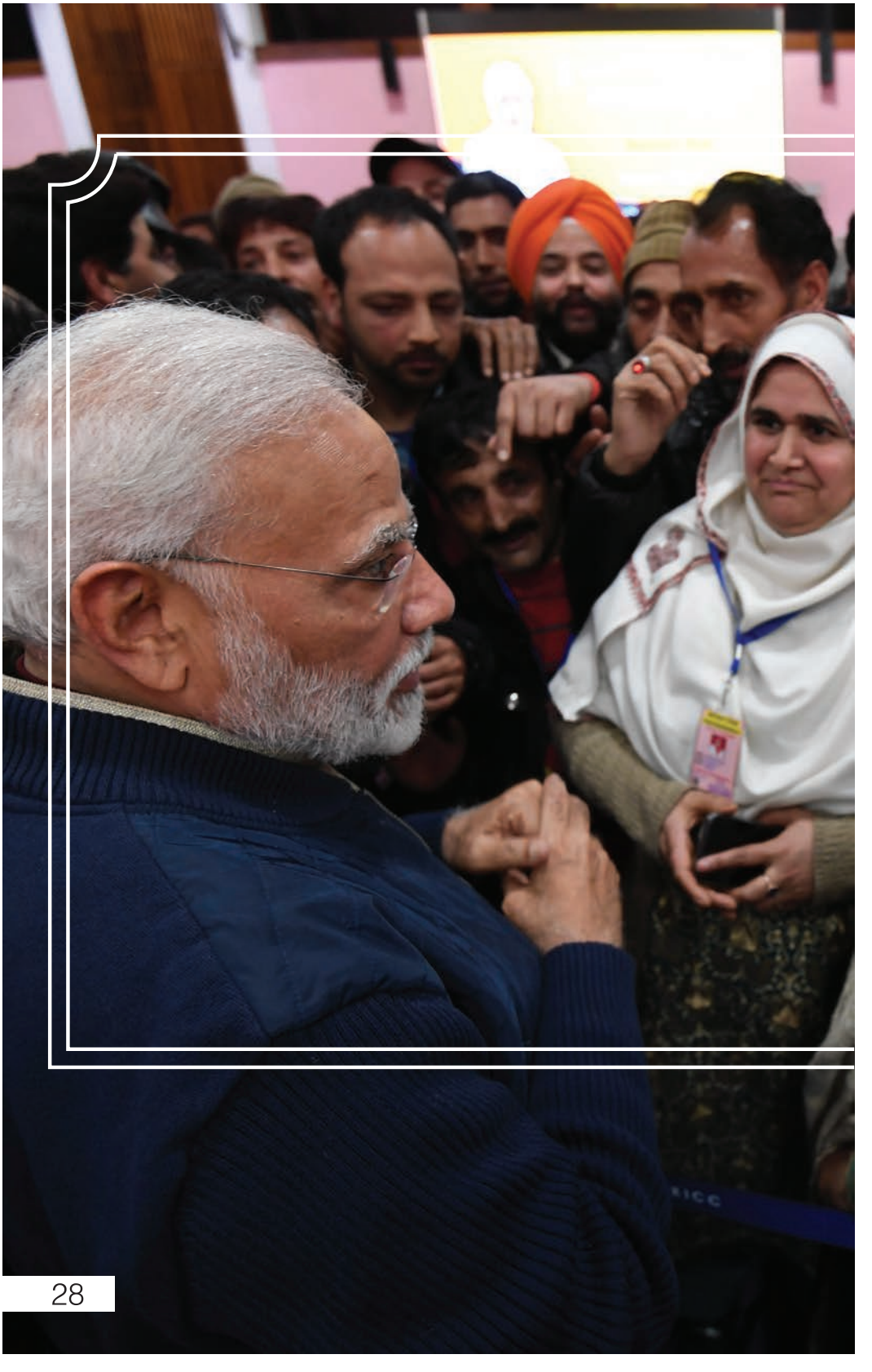

" मैं हमारी उन बेटियों को उपहार देना चाहता हूं, जो देश के लिए काम करना चाहती हैं। लालकिले की प्राचीर से, आज मैं घोषणा करता हूं कि हमारे रक्षा बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा चयनित महिला अधिकारियों के पास अब स्थायी कमीशन प्राप्त करने का विकल्प होगा।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जम्मू-कश्मीर
में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुए

संविधान की धारा 370 के समापन के साथ जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के विरूद्ध कई भेदभावपूर्ण कानूनों एवं प्रावधानों की समाप्ति हो गई।

धारा 35A की समाप्ति से, जम्मू-कश्मीर की महिलाएं अब भू-संपदा की खरीद कर सकती हैं तथा अप्रवासी से विवाह करने के बावजूद भी, बच्चों के नाम संपत्ति हस्तांतरित कर सकती हैं।

बाल विवाह के विरूद्ध कानून जो धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए लागू नहीं थे, अब वे भी लागू हैं।

मैं हमारी उन बेटियों को उपहार देना चाहता हूं, जो देश के लिए काम करना चाहती हैं। लालकिले की प्राचीर से, आज मैं घोषणा करता हूं कि हमारे रक्षा बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा चयनित महिला अधिकारियों के पास अब स्थायी कमीशन प्राप्त करने का विकल्प होगा।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वर्दीधारी बलों में
पहचान बनाने वाली महिलाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2018 को लालकिले की प्राचीर से सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन प्रदान करने की घोषणा की।

भारतीय वायुसेना में महिलाओं की ऊंची उड़ान

एक ऐतिहासिक कदम के तहत, तीन महिला युद्धक पायलटों को 2018 में भारतीय वायुसेना में युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया गया, जो अग्रणी भूमिकाएं निभाने में महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह, अवनि चतुर्वेदी और भावना कंठ युद्धक मिशनों पर लड़ाकू जेट विमानों में उड़ान भरने के लिए योग्य भारतीय वायुसेना की पहली महिलाएं बनीं।

THE TIMES OF INDIA

Permanent commission for women in more branches of military soon

The PM promised a transparent selection process for women via SSC

hindustantimes

'Nurtured the dream as a 10-yr-old': Indian Navy's first woman pilot Shivangi

Shivangi - Indian Navy's first woman pilot - hails from an ordinary farmer's family. Her father, Hari Bhushan Singh, is a school teacher and in-charge principal of a government high school for girls; and mother Priyanka a home-maker.

FINANCIAL EXPRESS

PM Narendra Modi meets Navy women officers selected for Navika Sagar Parikrama, wishes them luck

livemint

The Corps of Military Police is responsible for preserving "good order and discipline and to prevent breaches of the same by persons serving in or attached to the regular Army". (HT)

Army offering jobs in military police to women for the first time

Updated: 25 Apr 2019, 11:25 AM IST

The Indian EXPRESS

Indian Air Force inducts first batch of women pilots into its fighter squadron

The women fighter pilots will go to Bidar in Karnataka for their stage III training for a year on Hawk advanced jet trainers, before they get to fly supersonic warplanes.

THE NEW INDIAN EXPRESS

Captain Tania Shergill to become first woman parade adjutant for Republic Day parade

Commissioned in March 2017 from the Officer Training Academy, Chennai, Shergill is an electronics and communications graduate, they said.

14th January 2020 01:27 PM

Representational Image (EPS | Shekhar Yadav)

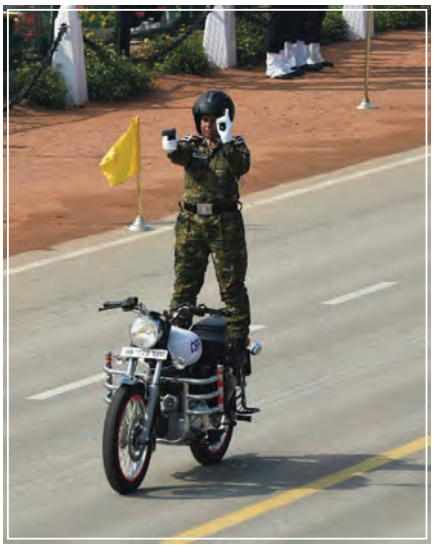

हवा हो या समुद्र

भारतीय महिलाएं अग्रणी

शॉर्ट सर्विस मिशन के माध्यम से नौसेना में शामिल की गई महिलाएं अब मेधाविता के आधार पर स्थायी कमीशन में भर्ती के लिए पात्र हैं।

सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी दिसंबर, 2019 में सेवा में शामिल होकर नौसेना की पहली महिला पायलट बनीं।

भारतीय महिलाएं

अर्द्धसैनिक बलों में अग्रणी

प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने भारत के अर्द्धसैनिक बलों में महिला अधिकारियों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की है।

जनवरी 2016 में, सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सिपाही के पदों की भर्ती हेतु महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

पुलिस बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने नए कदम उठाए हैं।

2015 में, सरकार ने 7 केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बलों में अराजपत्रित पदों में महिलाओं की सीधी भर्ती को मंजूरी दी।

दिल्ली में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए सिर्फ-महिलाओं की स्वात कमांडो टीम भी गठित की गई।

इस महिला स्वात की सभी कमांडो पूर्वोत्तर भारत की हैं।

पूरे भारत तथा विदेश के विशेषज्ञों से लगभग 15 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद, यह टीम शहरी क्षेत्रों में बंधक संकटों तथा आतंकवादी हमलों का उत्तर देने के लिए तैयार है।

एमपी-5 सबमशीन गनों तथा ग्लॉक-21 पिस्टलों से लैस, बल की सभी सदस्य इजराइली क्राव मागा में भी निपुण हैं, जो हथियार के बिना मुकाबला करने का एक तरीका है।

मीनाक्षी अम्मा

78 वर्षीया मीनाक्षी अम्मा कलारीपयट्टू की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाली सबसे उम्रदराज महिला हैं। वे उस मौलिक सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं कि महिलाएं मजबूत है तथा यदि वे अपनी रक्षा करने का निर्णय लेती हैं तो कोई भी उनकी गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने सैकड़ों लड़कियों को मार्शल आर्ट में आत्मरक्षा की कला प्रदान की है और उनमें आत्मविश्वास की स्थापना करके उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाया है।

मीनाक्षी अम्मा प्रत्येक महिला में मौजूद शक्ति की भावना की प्रतीक हैं।

4 संरक्षा एवं सुरक्षा

महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत की नारी शक्ति का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सकता यदि वे निजी और सार्वजनिक स्थलों पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। महिलाओं का सम्मान करने वाला समाज ही प्रगति और उत्थान करता है।

जब महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करेंगी तभी उनका आत्मविश्वास जगेगा और वे नए भारत के विकास में योगदान कर सकेंगी। जब सरकार महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेगी तब इससे बाधाओं को दूर करने और महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदलने में मदद मिलेगी।

महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों की गंभीरता को समझते हुए उनके लिए एक सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कानूनों, योजनाओं और कार्रवाइयों के जरिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।

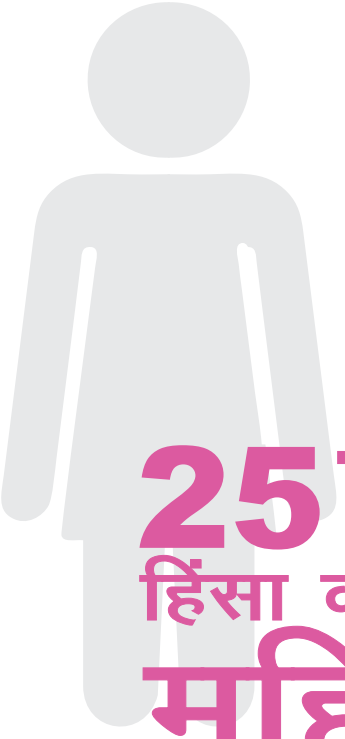

कॉल 181
महिला हेल्पलाइन
ADVICE- RESCUE- COUNSELLING

25 लाख हिंसा की शिकार महिलाएं

अप्रैल 2015 में महिला हेल्पलाइन नंबर

181

की शुरूआत के बाद से इससे लाभान्वित हुईं।

संकट में फंसी

महिलाओं के लिए मदद

वन स्टॉप केंद्र हिंसा की शिकार महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी परामर्श, पुलिस मदद, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय मुहैया कराता है। दिसंबर 2019 तक 728 वन स्टॉप केंद्रों को मंजूरी दी गई और 595 वन स्टॉप केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है।

स्वाधार गृह भी परित्यक्त महिलाओं, विधवाओं, मानव तस्करी से छुड़ाई गई महिलाओं और ऐसी ही अकेली पड़ गई महिलाओं को अस्थायी आश्रय देने का काम कर रहा है। 550 से अधिक स्वाधार गृहों के जरिए 17,000 से अधिक ऐसी महिलाओं को लाभ पहुंचा है।

महिला हेल्पलाइन योजना के सार्वजनीकरण से हिंसा की शिकार महिलाएं 181 नंबर डायल कर समय पर मदद पाने में सक्षम हुईं हैं। इससे जून, 2019 तक 25 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुईं हैं।

"बेटियां घर देर से वापस आती हैं तो माता-पिता उनसे पूछते हैं कि वो कहां थी। लेकिन, क्या वो अपने बेटों से भी ऐसी पूछताछ करते हैं। आखिरकार, बलात्कार जैसा घृणित काम करने वाला आदमी भी किसी का बेटा है। माता-पिता के रुप में क्या हम कभी अपने बेटों से पूछते हैं कि वो कहां जा रहा है। जहां हम अपनी बेटियों से पूछताछ करते रहते हैं तो अपने बेटों के मामले में भी ऐसा पैमाना क्यों नहीं अपनाते हैं?

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी"

जघन्य अपराधों के लिए कठोर दंड

भारतीय दंड संहिता में निर्णायक संशोधन से 12 साल से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार के मामले में मृत्यु दंड दिया जाना सुनिश्चित हुआ है।

16 साल से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार के मामले में कारावास की सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। इस तरह के कदमों से अपराधियों के दिमाग में ऐसा करने से बचने का भाव आएगा और ऐसी संस्कृति विकसित होगी जो महिलाओं की गरिमा का सम्मान करे।

सितंबर, 2018 में यौन अपराधों पर एक राष्ट्रीय आंकड़ा जारी किया गया था।

सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण की ओर

सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू होने के बाद

शी-बॉक्स सुविधा अब निजी संस्थानों के लिए भी उपलब्ध है।

अब सभी महिला कर्मचारियों के लिए उनके संगठन के बाहर एक मंच उपलब्ध है जहां वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

यौन उत्पीड़न पर

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए शी- बॉक्स

यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराने और उन पर हुई कार्रवाई की स्थिति का पता लगाने के लिए 2017 में शुरू यौन उत्पीड़न ई-बॉक्स अब वरदान साबित हो रहा है। मामलों का ऑनलाइन दर्ज किया जाना और उनका सीधे उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाना डिजिटल इंडिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दिसंबर, 2019 तक कुल 513 मामले दर्ज किए गए और 203 मामलों का निपटान किया जा चुका है। महिला सुरक्षा पर निर्णायक कार्रवाई।

महिला सुरक्षा पर निर्णायक कार्रवाई

महिलाओं की सुरक्षा के लिए

निर्भया कोष

वर्ष 2014 से पहले अनुपयोगी रहे निर्भया कोष का उपयोग अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अवसरंचना को उन्नत बनाने, नई प्रौद्योगिकी तथा भारत में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में किया जा रहा है।

दिसम्बर, 2019 तक कुल 7000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये, जिसमें त्वरित न्याय के लिए 1,023 फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना शामिल है।

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने और सुदृढ़ बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

निर्भया कोष के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी बस तथा मोबाइल ऐप बनाए गए, ताकि यह महिला और पुलिस के बीच सम्पर्क का काम कर सके। इसके लिए नवम्बर, 2019 तक 16.23 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

पूरे विश्व में सार्वजनिक परिवहन को महिलाओं के लिए सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। मेट्रो महिलाओं के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और सुरक्षित परिवहन का साधन है।

भारत में भी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर फोकस किया जा रहा है।

भारत के 11 शहरों में मेट्रो सेवा दी जा रही है ...
2025 तक 25 शहरों में मेट्रो सेवा संचालित होगी

इससे सार्वजनिक स्थलों पर
महिलाओं की सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा

अवैध-
व्यापार विधेयक प्रस्तुत

महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले जघन्य अपराधों को रोकने के लिए अवैध व्यापार विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रकार के गैर-कानूनी व्यापार पर नजर रखी जाए और त्वरित न्याय प्रदान किया जाए।

विधेयक में बलात् श्रम, वेश्यावृत्ति, यौन शोषण, जबरन विवाह जैसे विभिन्न अवैध कार्यों को शामिल किया गया है और इनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

विशेष न्यायालयों की स्थापना के साथ सरकार के सभी तीन स्तरों - जिला, राज्य और केन्द्र को जिम्मेदारी देता है। यह विधेयक पीड़ितों के पुनर्वास तथा पुनर्वास गृह बनाने का प्रावधान करता है।

मदुरै चिन्ना पिल्लई

मदुरै चिन्ना पिल्लई ग्रामीण वित्त पोषण में पथ-प्रदर्शक हैं, जिन्होंने अपने माइक्रोफाइनेंस आंदोलन 'कलनिजम' के माध्यम से तमिलनाडु के पुल्लुचेरी गांव में गरीबी के कुचक्र को तोड़कर रख दिया। वह 60,000 महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने और राष्ट्रव्यापी सामुदायिक बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने में सहायक थीं।

चिन्ना पिल्लई ने स्व-उद्यम के माध्यम से अपने सपनों को साकार बनाने के लिए महिलाओं में दृढ़ता का भाव विकसित किया।

5 #भारत की लक्ष्मी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं भारत की विकासात्मक गति का शीर्ष बल बनें, मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाएं हैं। इनमें पहला कदम महिलाओं को देश की औपचारिक वित्तीय प्रणाली में समान भागीदार बनाना और उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में काम करना है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना को व्यापक सफलता मिली है। इसके तहत 38 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। इसकी सफलता का मूल आधार इस योजना के तहत भारी संख्या में महिलाओं के खाते खुलना रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी सूक्ष्मवित्त (माइक्रोफाइनांस) पहलों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है। पीएम आवास योजना में महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता देकर उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत की गई है। मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं का चाहे वह जनधन, मुद्रा या आवास हो, मुख्य पहलू इन योजनाओं में महिलाओं की भारी भागीदारी रहा है। इससे महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सम्मान सुरक्षित हुआ है और उन्हें अपना स्वयं भाग्य विधाता बनने के लिए एक मजबूत नींव उपलब्ध हुई है।

38 करोड़ जन-धन खाता धारकों में 53 प्रतिशत महिलाएं हैं

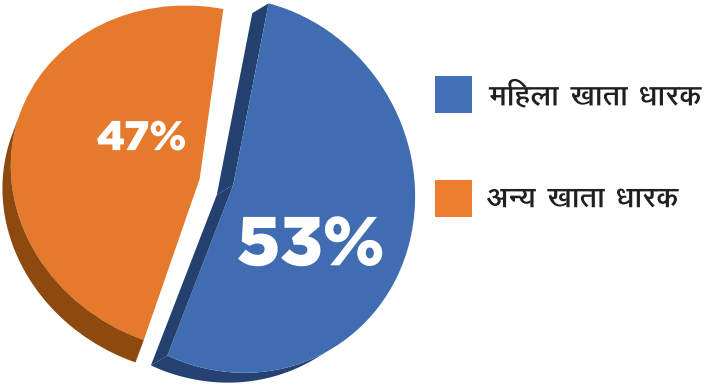

अपने बैंक खातों का नियमित रूप से उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 3गुना हुआ

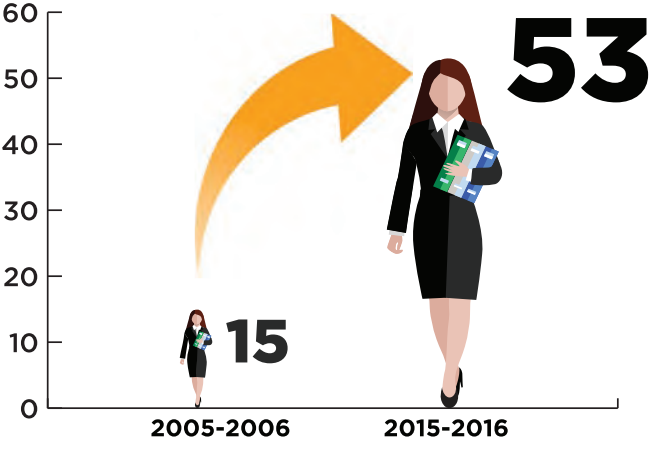

वर्ष (स्रोत : एनएचएफएस-3, एनएचएफएस-4)

वित्तीय समावेशन

महिलाओं की व्यापक सफलता

पीएम जन-धन योजना को समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने और इसे पहुंच के योग्य बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

इस योजना में बैंक खाते, धन भेजने, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच शामिल है।

38 करोड़ जन-धन योजना लाभार्थियों में 53 प्रतिशत महिलाएं हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से संबंधित जन-धन खाता धारकों को 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है।

स्वीकृत किये गए मुद्रा ऋणों का

70 प्रतिशत

महिला उद्यमियों से संबंधित है

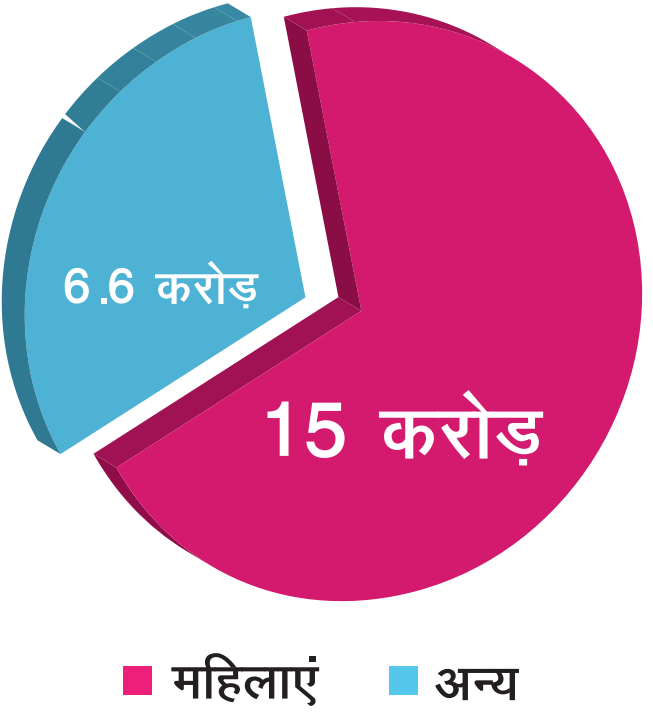

*दिसंबर 2019 के अनुसार

महिला उद्यमियों के लिए

सबसे अधिक मुद्रा लोन ऋण स्वीकृत किये गए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत की गई थी। मुद्रा ऋण का एक मुख्य लाभ यह है कि कर्जदार को कोई गारंटी देने या कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।

सभी स्वीकृत मुद्रा ऋणों में महिला उद्यमियों का हिस्सा 70 प्रतिशत है।

दिसंबर 2019 के अनुसार महिला उद्यमियों को 15 करोड़ ऋण मंजूर किये गए हैं। यह योजना की शुरूआत से लेकर 4 वर्षों के दौरान दिये गए ऋणों से 3.79 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है।

तमिलनाडु की तमरई मूर्ति ने अपनी छोटी बेटी के साथ गारे-मिट्टी के बने कच्चे घर में अनेक वर्ष गुजारे हैं। बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना आई जिसने उसके जीवन को बदल दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में

महिलाओं को वरीयता दी गई

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के सिर पर छत की सुरक्षा और उनके लिए सस्ते घरों के निर्माण द्वारा वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई है।

जो घर महिलाओं के नाम पर हैं उन्हें अधिक सब्सिडी, कम ब्याज दर और अधिक कर कटौतियां जैसी रियायतें दी जाती हैं।

मार्च, 2019 तक स्वीकृत किये गए घरों में से 27.06 लाख घर महिला लाभार्थियों के नाम से स्वीकृत किये गए हैं और 35 लाख घर पति और पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृत किये गए हैं।

पीएमएवाई(जी) के तहत विधवाओं के नाम 5.75 लाख घर स्वीकृत किये गए हैं।

असम के जोरहाट जिले में एक कच्चे घर में अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला तियाद को बाढ़ में अपना घर बहने का डर लगातार सता रहा था। लेकिन अब पीएमएवाई योजना का लाभ उठाने के बाद उसके घर का परंपरागत तरीकों का उपयोग करके निर्माण किया गया। इस प्रकार उसका घर बाढ़ और भूकंप दोनों से सुरक्षित हो गया है।

महिलाएं मनरेगा में सबसे आगे हैं

मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत महिलाओं की भागीदारी सुधारने पर विशेष ध्यान दिया है।

हालांकि सांविधिक रूप से महिलाओं की केवल न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी अपेक्षित है लेकिन मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक है।

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मनरेगा में भाग ले रही गर्भवती महिलाओं को उनके घरों के आसपास ही कम मेहनत वाले काम दिये जायेंगे।

डॉ. आनंदीबाई जोशी

अपनी ज्ञान की खोज और मेडिसिन के लिए जुनून के कारण डॉ. आनंदीबाई जोशी ने मेडिसिन के अध्ययन के लिए सामाजिक परंपराओं की चुनौतियों का सामना किया। वो पहली भारतीय डॉक्टर हैं, जो वूमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेन्सिलवेनिया से स्नातक बनी और जिसने 19वीं शताब्दी में अनेक बाधाओं को पार किया। देश में वापस आने पर वे स्थानीय एल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल के महिला वार्ड की फिजिशियन-इन-चार्ज बनीं। वे महिलाएं, जो अपना इलाज कराने में भी संकोच करती थीं उनकी उपस्थिति में सहज महसूस करने लगीं।

डॉ. आनंदीबाई जोशी ने अनेक महिला डॉक्टरों के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता खोलने के साथ-साथ महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया।

6 स्वास्थ्य और कल्याण

अतीत में जहां महिलाओं के स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को अलग-थलग करके देखा जाता था, वहीं मोदी सरकार ने महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए 'बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित' करने की दिशा में काम किया है।

चाहे वह पोषण हो अथवा मासिक धर्म स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मातृ स्वास्थ्य हो या यहां तक कि रसोई घर में स्वच्छ हवा जैसे बुनियादी बातें हों, मोदी सरकार ने इनके लिए लीक से अलग हटकर दृष्टिकोण अपनाया है। 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करने के साथ स्वच्छ भारत जो बड़ी स्वच्छता क्रांति लेकर आया है वो पहले ही अच्छी तरह जाना जाता है और वैश्विक स्तर पर सराहा भी गया है।

इसके अलावा पोषण के लिए धन में वृद्धि, सैनिटरी पैड को सस्ता करना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं के लिए स्वच्छ खाना पकाने की गैस मुहैया कराना और गर्भपात की समयावधि को बढ़ाना उन उपायों में से कुछेक हैं जो इस सरकार ने किए हैं और जिन्होंने पूरे भारत की लाखों महिलाओं के जीवन को सीधे तौर पर छुआ है।

सैनिटरी पैड्स

महिलाओं के लिए निजी स्वच्छता को ज्यादा सुलभ और सस्ता बनाने के लिए सैनिटरी पैड्स की कीमत को घटाकर 1 रुपये तक ले आया गया है और जिन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है।

महिलाओं का पोषण सुनिश्चित करने के लिए पोषण अभियान

गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए यह एक प्रमुख योजना है।

तीन वर्षों में पोषण अभियान के अंतर्गत 7,411 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य 2022 तक 15-49 वर्ष के आयु समूह की महिलाओं और किशोरियों में रक्त की कमी को कम करना है।

बच्चे के जन्म
के बाद पहले 42 दिनों के दौरान
एक आशा कार्यकर्ता कम से कम छह बार
घर आती थी। अब वह 15 महीनों में 11 बार
उस नवजात बच्चे के विकास और स्वास्थ्य का
पता लगाने के लिए घर आती है। मुझे यकीन
है कि उस बच्चे के प्रति आपका प्यार और
स्नेह यह सुनिश्चित करेगा कि भारत को
उत्कृष्ट नागरिक मिलें।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सशक्त

आशा कार्यकर्ता

1.06 करोड़ से अधिक 'आशा' (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और आशा सहायकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर किया गया है।

10.22 लाख आशा कार्यकर्ताओं के लिए नियमित मासिक प्रोत्साहन राशि दोगुनी करके 2,000 रुपये कर दी गई है।

6 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन से युक्त किया गया है ताकि वे 10 करोड़ से अधिक परिवारों के पोषण की स्थिति अपलोड कर सकें।

आयुष्मान भारत

आयुष्मान महिला

यह महिलाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित करने की योजना है ताकि वे कैंसर जैसी बीमारियों की जांच के लिए आगे आएं।

अब तक 70 लाख महिलाओं ने स्तन कैंसर की जांच करवाई है जो हमारे यहां व्याप्त सामाजिक अनिच्छा को देखते हुए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

सरवाइकल कैंसर के लिए 30 लाख महिलाओं की राष्ट्रव्यापी जांच की गई है।

> 2020 तक पूरे भारत में एलपीजी की पहुंच प्रदान करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह ऊर्जा से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक आर्थिक मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा है।
>
> - आईईए के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल

स्वच्छ ईंधन स्वच्छ हवा

गरीब परिवार की वयस्क महिलाओं के नाम पर 8 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी किए गए।

नया एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,600 रुपये तक की नकद सहायता।

लकड़ी, गाय के गोबर और चारकोल के धुएं से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों की रोकथाम।

महिलाओं को ईंधन की तलाश करने से मुक्ति मिली, अब वे बच्चों के साथ या अतिरिक्त कमाई करने में अधिक समय बिता सकती हैं।

मातृ स्वास्थ्य में सुधार

एक स्वस्थ और सुरक्षित मातृत्व हर महिला का अधिकार है। भारत में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सहायता में निरंतर सुधार देखा गया है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है, क्योंकि वह मानती है कि एक नया भारत तभी संभव है जब स्वस्थ महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दें।

मातृ मृत्यु दर में कमी

अस्पतालों तक पहुंच में कमी, अनियमित जांच और कुशल डॉक्टरों की कमी के कारण अक्सर ऊंची मृत्यु दर होती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने पिछले कुछ वर्षों में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में लगातार गिरावट को सुनिश्चित किया।

मातृ मृत्यु दर 2011-2013 में 1 लाख जीवित जन्मों पर 167 थी, वहीं 2014- 2016 में ये गिरकर 130 और 2015-17 में 122 हो गई।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रसवपूर्व देखभाल स्वस्थ मातृत्व की कुंजी है। यह गर्भावस्था से संबंधित मुद्दों का जल्द पता लगाकर जटिलताओं की संभावना को कम करती है।

एक जन आंदोलन के रूप में प्रत्येक माह की 9 तारीख को मुफ्त जांच के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान निजी चिकित्सकों की सेवाएं प्रदान करता है।

देश भर में 12,900 स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में 2.26 करोड़ से अधिक महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच।

9.18 लाख उच्च जोखिम वाले गर्भधारणों की पहचान की गई और इलाज किया गया।

भारत में मातृ मृत्यु दर

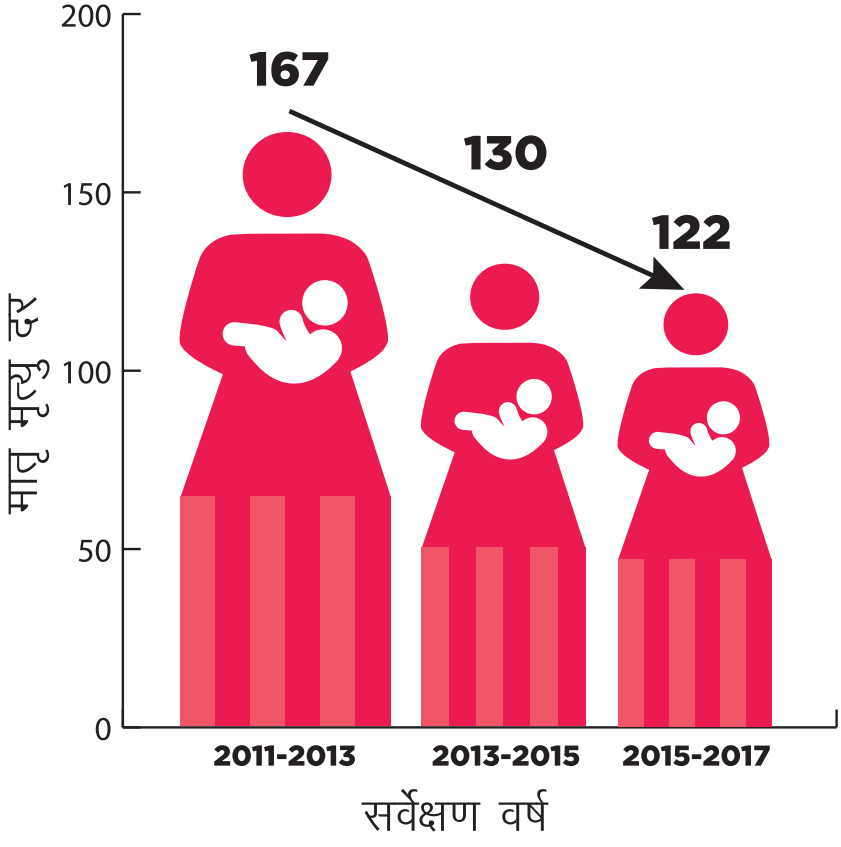

जब एक मां सुनती है कि उसके बच्चे ने बुद्धिमानी भरी शिक्षा का पालन किया है तो वो उससे भी ज्यादा खुशी महसूस करती है जितनी उसने उसे जन्म देते समय की थी।

तिरुक्कुरल, श्लोक 69

प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना

गर्भावस्था के दौरान पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए महिलाओं को प्रति माह 5000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है।

ये पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया।

1.28 करोड़ से अधिक महिलाओं को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित कर सुनिश्चित सहायता प्रदान की गई।

> भारत 2030 की तय तारीख से काफी पहले मातृ और बाल स्वास्थ्य के लिए एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है।
>
> – नरेन्द्र मोदी

गर्भपात के लिए सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (संशोधन) बिल, 2020 ने गर्भपात की सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह की।

बलात्कार पीड़ितों, अनाचार पीड़ितों या अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए ये मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया गया।

मिशन इंद्रधनुष रोगों की रोकथाम में महिलाओं की मदद करता है

सुरक्षित मातृत्व और जीवन में बाद के चरणों में बच्चों के बीच घातक बीमारियों को रोकने के लिए गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण महत्वपूर्ण है।

2014 में शुरू होने के बाद से मिशन इंद्रधनुष के तहत लक्षित टीकाकरण अभियान चलाए गए हैं।

फरवरी 2020 तक 690 जिलों में 91.45 लाख गर्भवती महिलाओं और 3.61 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया।

दिसंबर 2019 में गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया ताकि टीकाकरण कवरेज को वांछित स्तर तक ले जाया जा सके।

बेहतर बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए
मातृत्व अवकाश
को बढ़ाया गया

2017 में मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद भारत सबसे अधिक मातृत्व अवकाश देने में तीसरे स्थान पर पहुंचा।

इसने संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए पूरी तरह से वेतन सहित मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दिया।

ये प्रावधान दो बच्चों के जन्म के लिए लागू है।

किलकारी
स्वास्थ्य का ऑडियो मैसेंजर

डिजिटल इंडिया को भुनाते हुए अब प्रौद्योगिकी का उपयोग समय पर चिकित्सा अपडेट देने के लिए किया जा रहा है।

किलकारी मोबाइल एप्लिकेशन गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को लेकर मुफ्त ऑडियो संदेश भेजती है।

स्वस्थ मातृत्व का संदेश फैलाते हुए इसमें 16.93 करोड़ से अधिक सफल कॉल किए गए हैं।

“

मिशन इंद्रधनुष जिस गति और पैमाने पर काम कर रहा है, वो निवारक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में एक नया प्रतिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित गर्भावस्था को एक जन आंदोलन बना रहा है।

”

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

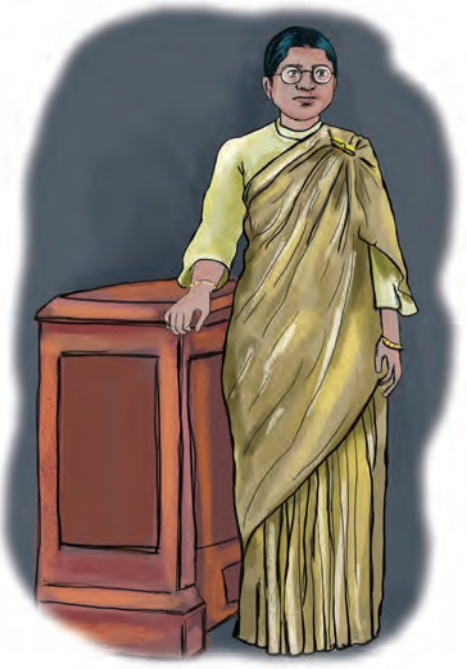

मुथुलक्ष्मी रेड्डी

चिकित्सा में स्नातक करने वाली भारत की पहली महिला होना, किसी विधायी निकाय की अध्यक्षता करने वाली दुनिया की पहली महिला होना और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होना डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी की अनुकरणीय उपलब्धियों में से कुछेक हैं।

डॉ. मुथुलक्ष्मी न केवल एक चिकित्सा पेशेवर और समाज सुधारक थीं बल्कि एक उद्यमी भी थीं जिन्होंने पूरे देश में दूसरा और दक्षिण भारत में पहला व्यापक कैंसर केंद्र अड्यार कैंसर संस्थान की स्थापना की थी।

मुथुलक्ष्मी रेड्डी महिलाओं के बीच अपने क्षितिज का विस्तार करने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उद्यमशीलता की भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं।

7 महिला नेतृत्व 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की ओर

भारत की महिलाओं की उद्यमिता भावना को उभारने के लिए उन्हें सशक्त बनाना मोदी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में एक है। महिलाएं अपने-अपने क्षेत्रों में नेता के रूप में उभर रही हैं और 5 ट्रिलियन डॉलर की आधारशिला को मजबूत बनाने में सहायता कर रही हैं।

मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि महिला उद्यमिता के विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को रोकने वाली बाधाओं को दूर किया जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने के लिए उनकी क्षमता को उभारा जाए।

एसएचजी, एमएसएमई तथा स्टार्टअप को अधिक ऋण सुनिश्चित करने के प्रावधान, सुरक्षित कार्यस्थल तथा उचित वेतन सुनिश्चित करने वाले कानूनों से महिलाओं को अपनी पसंद के काम प्रारंभ करने का मार्ग आसान हुआ है, चाहे वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करना हो या रोजगार सृजक या स्वयं उद्यमी बनना हो।

स्टैंडअप इंडिया के कुल ऋण का 83 प्रतिशत महिला उद्यमियों को दिया गया

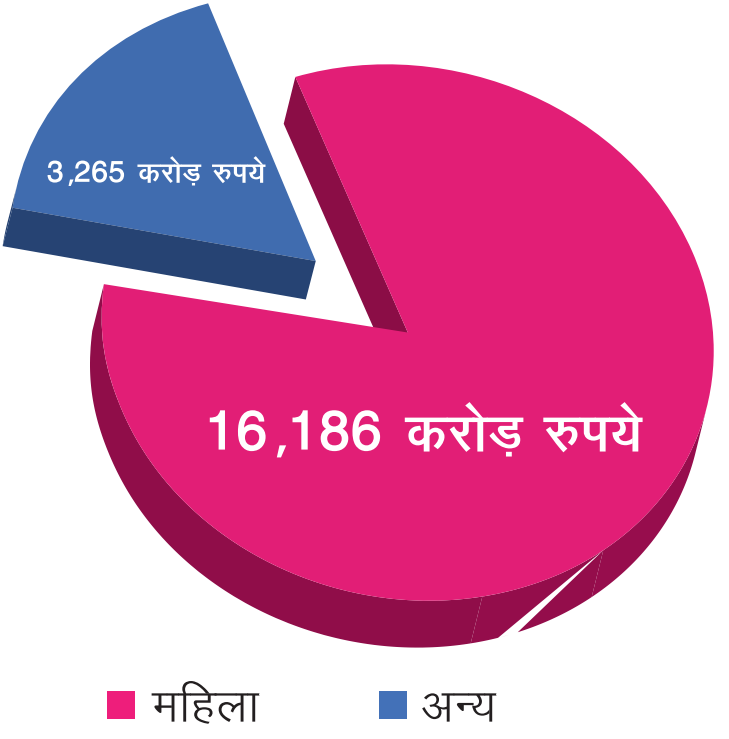

दिसंबर 2019 तक

स्टैंडअप इंडिया **महिला उद्यमियों को** प्रोत्साहित करता है

स्टैंडअप इंडिया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से एक महिला को 10 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये के बीच ऋण प्राप्त करने में सहायक है।

अब तक आकांक्षी महिला उद्यमियों को कुल 19,451 करोड़ रुपये के ऋण में से 16,186 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

31 दिसंबर, 2019 तक स्टैंडअप इंडिया से 70,808 महिला उद्यमी लाभान्वित हुई हैं।

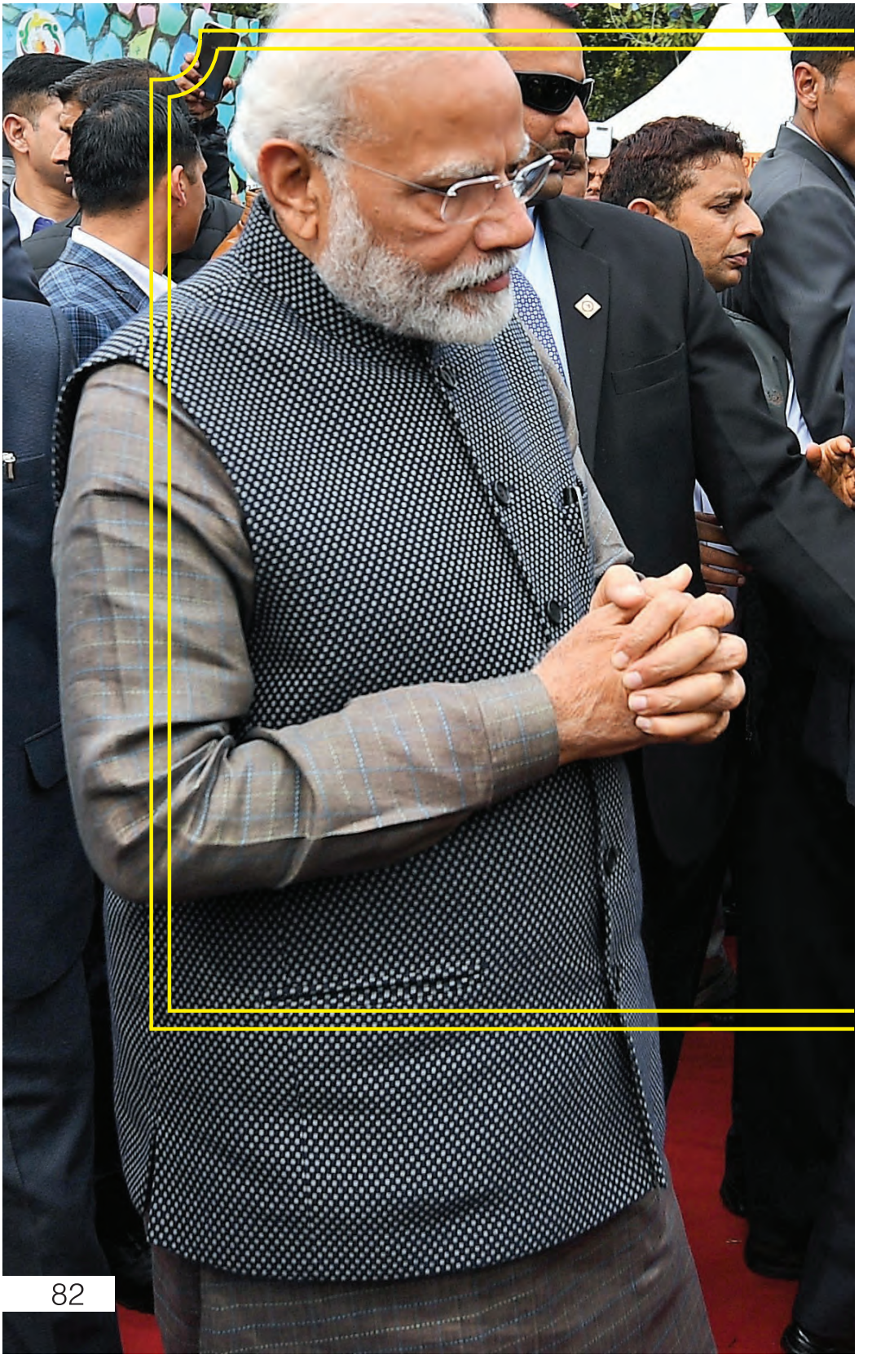

अधिक महिलाओं को रोजगार देने के लिए

भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना

केन्द्रीय बजट में औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार प्रोत्साहन के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई।

सरकार ने ईपीएफओ में महिला कर्मचारियों के अंशदान को वर्तमान 12 प्रतिशत या 10 प्रतिशत की जगह रोजगार के पहले तीन वर्षों के लिए अंशदान घटाकर 8 प्रतिशत किया।

इसे ईपीएफओ में नियोक्ता की ईपीएफओ हिस्सेदारी को बढ़ाये बिना लागू किया गया और इस तरह औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को अधिक रोजगार देने के लिए कंपनियों को और प्रोत्साहित किया गया।

इससे महिलाएं अधिक वेतन घर ले जाने में सक्षम हुईं। इससे नियमित/वेतन रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।

अपने पति से अधिक या बराबर आय अर्जित करने वाली रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई

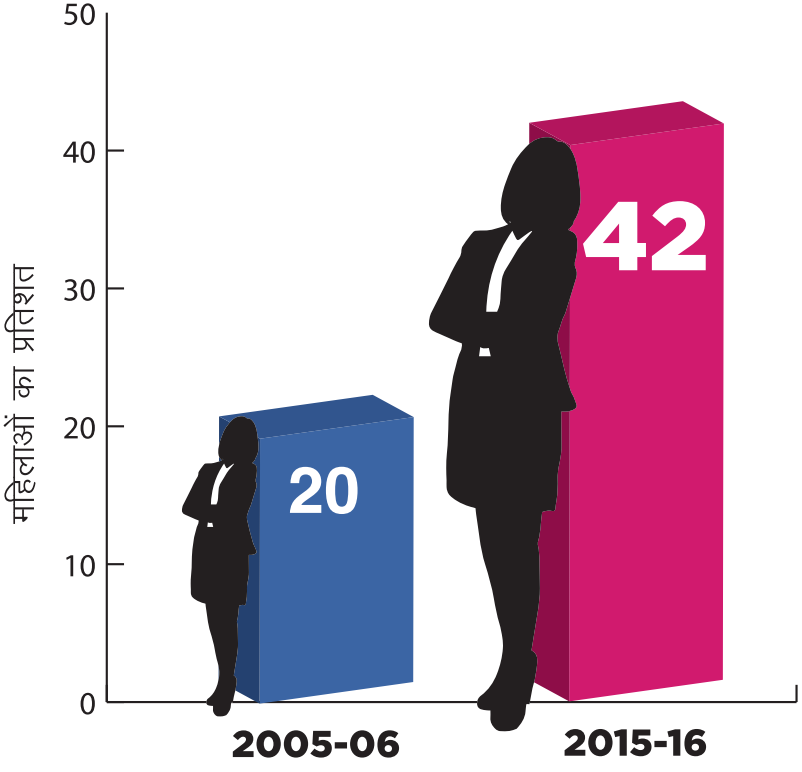

एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) एक तरह से गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए आर्थिक प्रगति का आधार बने हैं और महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक रूप से अधिक मजबूत बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह छोटे उद्यमियों तथा श्रमिकों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

- प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी

उचित वेतन और कार्य स्थिति सुनिश्चित

वेतन संहिता, 2019 अधिनियम तथा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता 2019 कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए अधिक सार्थक और उचित कार्य स्थल प्रदान कर रही हैं।

वेतन अधिनियम संहिता एकसमान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए कर्मचारियों के वेतन और भर्ती से संबंधित कार्यों में लैंगिक भेदभाव का निषेध करती है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता, 2019 ने एक उपाय लागू किया है, जिसमें महिलाएं रात्रि पाली में काम करने का विकल्प चुन सकती हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कवरेज को बढ़ाते हुए संहिता क्रेच जैसे कल्याणकारी प्रावधानों को भी निर्धारित करती है।

वेतन भोगी के रूप में काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत दोगुना हुआ

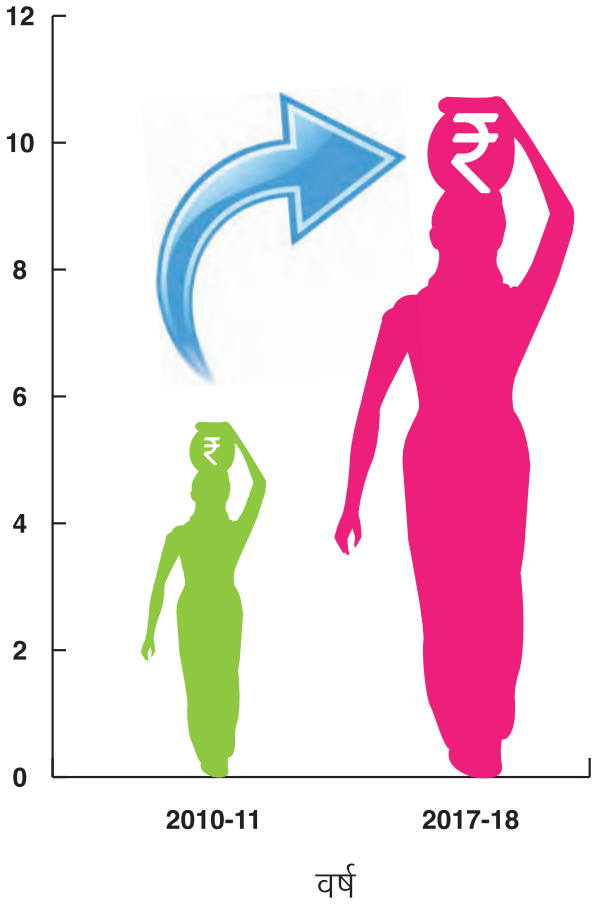

महिला एसएचजी
को सशक्त बनाना

केन्द्रीय बजट में महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए ग्रामीण भंडारण योजना में बैकवर्ड लिंकेज भंडारण क्षमता का प्रस्ताव किया गया।

मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रत्येक एसएचजी में एक महिला को एक लाख रुपये का ऋण मिलेगा।

महिला स्वयं सहायता समूह ब्याज अनुदान कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उद्यमी अरुलमोझी सवर्णन से मिले, जिनके थर्मोफ्लास्क का आदेश सरकारी ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से पीएमओ द्वारा दिया गया। उन्होंने मुद्रा ऋण की सहायता से अपना व्यापार प्रारम्भ किया और वह इस बात का जीवित उदाहरण है कि सरकार के सुधार किस तरह महिला उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं।

महिला एमएसएमई
का व्यापक विकास

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अधिक से अधिक महिला एमएसएमई उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास किये हैं।

सरकार ने यह निर्धारित किया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कुल खरीद में से कम से कम 3 प्रतिशत खरीदारी महिला एमएसएमई से करनी होगी।

वास्तव में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिए जाते हैं। योजना के तहत कुल मंजूर ऋणों का 70 प्रतिशत महिला एमएसएमई उद्यमियों को दिए गए हैं।

एमएसएमई में महिला स्वामित्व वर्ष 2011 में 13.72 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में अखिल भारतीय स्तर पर 19.5 प्रतिशत हो गया।

सीतारमण ने महिला स्वयं सहायता समूहों पर□ प्रोत्साहनों की बौछार की

05 जुलाई, 2019

"महिलाएं व्यावहारिक बुद्धिमता का उपयोग करती हैं, इससे उन्हें अपने व्यवसाय में धन की बचत करने और कुछ पूंजी बनाने में मदद मिलती है। यदि उनका व्यवसाय 6 महीने तक प्रणालीबद्ध रूप से चलता है और सरकार उन्हें सहायता देती है, तो इससे उन्हें बैंकों से संस्थागत वित्त प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।"

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

एसएचजी को मुद्रा : बजट 2019 ने महिला स्ट्रार्ट अप और ग्रामीण□व्यवसाय को प्रोत्साहित किया।□ महिलाओं के लिए अग्रणी कार्यक्रमों में बजट आवंटन में इस वर्ष

05 जुलाई, 2019

महिला उद्यमियों को डिजिटल बाजार प्रदान करना

महिला उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों/स्वयं सेवी संगठनों को समर्थन देने के लिए 2016 में ऑनलाइन ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म महिला ई-हाट प्रारम्भ किया गया। ई-हाट में 7,000 से अधिक उत्पाद और सेवाएं तथा 32,000 से अधिक महिला उद्यमी/स्वयं सहायता समूह/स्वयं सेवी संगठन हैं।

जीईएम प्लेटफॉर्म से 8,000 से अधिक महिला उद्यमी सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं।

जीईएम में 'वुमनिया' और 'स्वायत्त' प्रारम्भ किया गया, ताकि महिला उद्यमी और महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह जीईएम पर अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकें और बेच सकें।

साइना नेहवाल

विश्व की नंबर-1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारत में प्रत्येक एथलीट के लिए प्रेरणा साइना नेहवाल भारत की सर्वाधिक सफल और पारंगत खिलाड़ियों में से एक हैं।

अगली बड़ी चुनौती से कभी मुंह न मोड़ने वाली साइना नेहवाल तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं-ओलम्पिक्स, बीडब्ल्यूएफ चैम्पियनशिप तथा बीडब्ल्यूएफ जूनियर चैम्पियनशिप-में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं।

साइना नेहवाल अपने-अपने क्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिलने पर अपार सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं का मूर्त रूप हैं।

8

#Sheinspriesus

हर नए दिन के साथ भारत की महिलाएं नई चुनौतियों से जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं और फिर उनका डटकर सफलतापूर्वक सामना करती हैं। चाहे खेल का मैदान हो या विज्ञान का क्षेत्र, हर जगह भारत की बेटियों ने अपनी मातृभूमि का गौरव, सम्मान और गर्व बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है।

बदलते समय के साथ ही नजरिए में बदलाव लाने का आह्वान किया जाता रहा है और भारत की अत्यंत कामयाब महिलाओं के नेतृत्व में एक सामाजिक क्रांति ठीक हमारी आंखों के सामने इसे सुनिश्चित कर रही है। नई अनुकरणीय महिलाएं (रोल मॉडल) मनगढ़ंत धारणाओं को तोड़ रही हैं और ऐसे मानक स्थापित कर रही हैं जिनकी आकांक्षा हर महिला करती है।

हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करने के साथ ही भारत का भविष्य भारतीय महिलाओं के संसाधनों से परिपूर्ण और दृढ़प्रतिज्ञ हाथों में सकुशल एवं सुरक्षित प्रतीत होता है। भारतीय महिलाओं ने अब उन सभी बंधनों को तोड़ना शुरू कर दिया है जो उनकी प्रगति में अब तक बाधक साबित होती रही हैं। भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है।

प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने सिर्फ एक माह में ही अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं - **हिमा दास**

प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग में नम्बर वन का खिताब हासिल किया था - **साइना नेहवाल**

प्रथम भारतीय जिन्होंने 6 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है वह एक महिला है - **मैरी कॉम**

First ever Indian woman to win gold at a world event in wrestling – **Vinesh Phogat**

The second ever final finish in women's cricket world cup by India in 2017

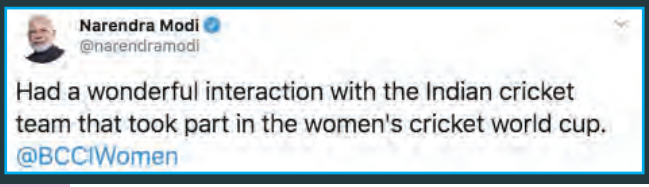

सबसे युवा महिला जिसने विश्व निशानेबाजी (शूटिंग) चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं वह एक भारतीय है

- मनु भाकर

QTR 3
25
TOL TF
3 4

58
TF TOL
0 3

प्रथम भारतीय जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड टूर फाइनल जीता है
- पी वी सिंधु

टेबल टेनिस में एशियाई स्तर का प्रथम पदक संयुक्त रूप से एक महिला ने जीता था
- मनिका बत्रा

ओलंपिक खेलों में भारतीय महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी वर्ष 2016 में हुई थी।

यह माना जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना एक बेहतर राष्ट्र और एक बेहतर सुव्यवस्थित समाज की कुंजी है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व से निश्चित तौर पर एक नया एवं बेहतर भारत नजर आ सकता है, जो तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है।

पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 46 प्रतिशत के अब तक के उच्चतम स्तर को छू गया है जो स्थानीय निकायों में महिलाओं की अत्यंत सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

livemint

Shooting down the ceiling - women in the army

3 min read . Updated: 19 Feb 2020, 11:32 PM IST

Surbhi Bhatia, Sriharsha Devulapalli

Women now have permanent commission in the Indian Army but remain a long way from equal representation in the armed forces, suggests data

निर्वाचित महिला सांसदों की सर्वाधिक संख्या (78) 17वीं लोकसभा में रही, जबकि पिछली लोकसभा में 64 महिला सांसद थीं।

तीन महिला न्यायाधीशों के साथ भारत के उच्चतम न्यायालय के इतिहास में आज सर्वाधिक महिला न्यायाधीश हैं।

'समुद्र पर कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण' में एक न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित प्रथम भारतीय महिला नीरू चड्ढा ने एशिया-प्रशांत समूह में सर्वाधिक मतों से प्रतिद्वंद्वियों को मात दी थी।

लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या

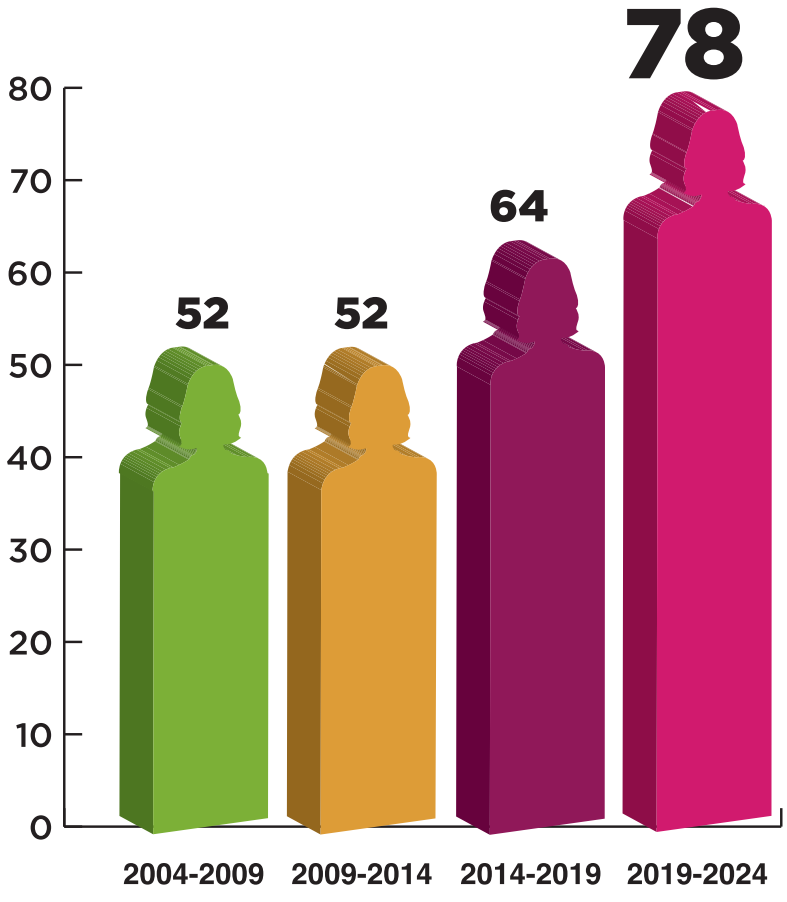

महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन की कमान संभाली थी और वे मिशन की निदेशक एवं परियोजना निदेशक थीं **- ऋतु करिधल और वनिता मुथैय्या।**

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को हर देश में सदैव काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत में उनके मार्ग में बाधाएं और भी ज्यादा रही हैं। हालांकि, इसके बावजूद वे हतोत्साहित नहीं हुईं क्योंकि वे हर दिन नई ऊंचाइयों को छूती रही हैं। भारत में 'स्टेम' शिक्षा में महिलाओं की संख्या बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है जिससे हमारी काबिल बेटियों की अगुवाई में भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं काफी प्रबल हो गई हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) विषयों में 44 प्रतिशत स्नातक महिलाएं ही हैं।

भारत में प्रथम रोटावायरस टीका एक महिला ने ही विकसित किया था - **गगनदीप कांग**

ऐसे कई स्थानों में एक ऐसा स्थान भी है जहां पक्षियों में मलेरिया होने का अध्ययन विशेषकर एक महिला द्वारा किया जा रहा है वह हैं - **फराह इश्तियाक**

सशस्त्र बलों का एक हिस्सा होना सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय रहा है और महिलाएं भी लम्बे समय से इसका हिस्सा बनने की आकांक्षा रखती रही हैं। महिलाओं की भूमिका एवं भर्ती में नये बदलाव होने और महत्वपूर्ण मिशनों की जिम्मेदारी सौंपे जाने से आज महिलाओं ने भी यह सही साबित कर दिखाया है कि वे पुरुषों से कमतर नहीं हैं, क्योंकि वे भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं।

भारतीय वायु सेना ने जंग लड़ने की भूमिकाएं निभाने हेतु भी महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं क्योंकि पहली बार तीन महिलाओं को जंग के मिशनों पर लड़ाकू विमानों को उड़ाने के योग्य माना गया है।

भारत की प्रथम महिला नौसेना पायलट सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी दिसंबर 2019 में इस सेवा से जुड़ीं।

भारत का गौरव 'आईएनएसवी तारिणी की समस्त महिला चालक दल' ने 254 दिनों के अभियान में पूरी दुनिया की सैर की और इसके साथ ही अपने टीम वर्क एवं विलक्षण नेतृत्व से विश्व को परिचित कराया।

उपलब्धियों के नये-नये शिखरों पर पहुंच कर भारत की महिलाओं ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है। अभियान और साहसिक खेल (एडवेंचर स्पोर्ट्स) का क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है क्योंकि भारत की बेटियों ने हर दिन अपनी नई एवं हैरतअंगेज उपलब्धियों से पहले की तुलना में देश का मान और भी अधिक बढ़ा दिया है।

इसरो की महिला वैज्ञानिक मंगला मणि ने अंटार्कटिका में 403 दिनों से भी अधिक समय तक निरंतर शोध कर देश का गौरव एवं मान बढ़ाया है।

दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को जीतने वाली सबसे युवा पर्वतारोही भारत की 12 वर्षीया बेटी काम्या कार्तिकेयन है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

#SheInspiresUs से सभी को प्रेरित करते हैं

भारत, देश के इंटरनेट यूजरों (नेटिजन) और देश की महिलाओं के लिए यह मार्च 2020 का पहला सप्ताह एक अनूठा सप्ताह रहा है।

इस सप्ताह की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन के साथ हुई कि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ देंगे, जबकि इसका समापन महिलाओं के लिए एक गहन और सशक्त संदेश के साथ हुआ है।

समूचा राष्ट्र केवल एक ही सवाल पूछ रहा था - क्या मोदी सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं?

छोड़ने का अर्थ दूर जाना नहीं

दुनिया की आधी आबादी यह अंदाजा लगाने में परेशान हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपनी योजना के बारे में अगले दिन ट्वीट किया।

उन्होंने कहा कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को सौंप देंगे जिनके जीवन और कार्य प्रेरणादायक रहे हैं।

उन्होंने राष्ट्र से आह्वान किया कि उन्हें ऐसी महिलाओं के बारे में अवगत कराएं।

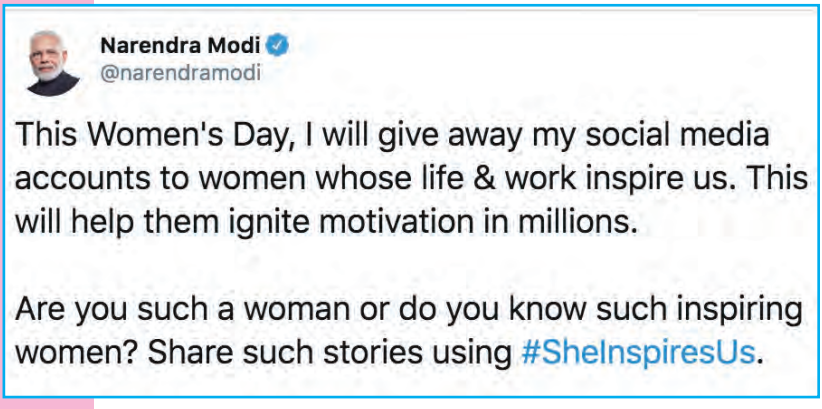

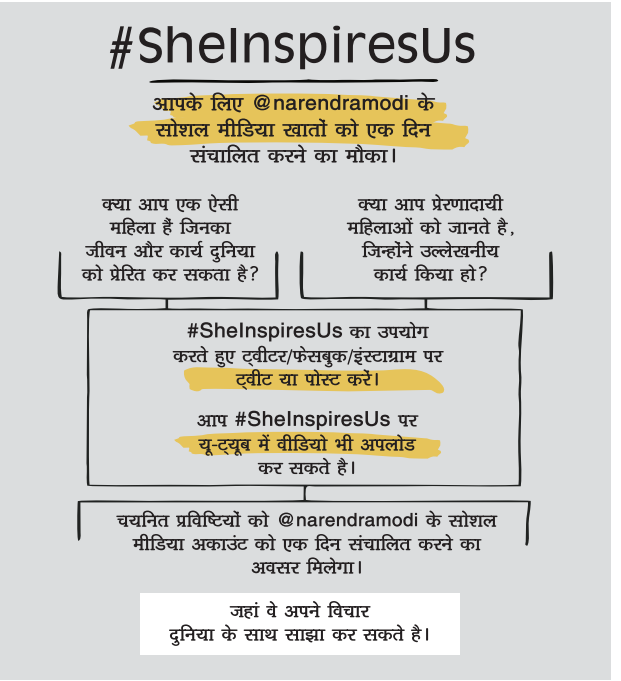

पूरे देश से उत्साहवर्धक परिणाम मिले।

लोगों ने #SheInspiresUs का उपयोग करते हुए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को नामांकित किया। इनमें ऑटो चलाने वाली महिलाओं से लेकर छोटे उद्यमियों तक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर आम गृहणियां तक शामिल थीं।

यह महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री मोदी ने सैकड़ों सुझावों में से सात महिलाओं को चुना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इन महिलाओं को प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई।

सात प्रेरणादायी महिलाएं

निम्न सात महिलाओं को चयनित किया गया थाः

डॉ. मालविका अय्यर- बम विस्फोट पीड़िता और दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता

स्नेहा मोहनदास- फूड बैंक इंडिया की संस्थापक और समाजसेवी

अरीफा ज़ान, कश्मीर- लुप्त प्राय कला नम्दा हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत, 100 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया।

कल्पना रमेश- जल संरक्षण कार्यकर्ता, हैदराबाद की झीलों को पुनर्जीवित करने और वर्षा जल संचय को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत।

विजया पवार- बंजारा महिला, जो पारम्परिक कढ़ाईयुक्त सामान बनाती हैं और इन्हें एसएचजी के माध्यम से बेचती हैं।

कलावती देवी- शौचालय निर्माण और महिलाओं के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत।

वीणा देवी- घर के अंदर खेती की शुरूआत की और बाद में अपने गांव की सरपंच बनीं।

सफल महिलाओं के जीवन से प्रेरणा की झलकियां

स्नेहा मोहनदास ने बताया कि कैसे उन्होंने बेघर लोगों को अपने फूड बैंकइंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया।

डॉ. मालविका अय्यर ने संकल्प और धैर्य की अपनी कहानी से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता से जुड़ी मान्यताओं को समाप्त करने की जरूरत है। दिव्यांगजनों को रोल मॉडल के रूप में दिखाते हुए युवाओं को जागरूक बनाया जाना चाहिए।

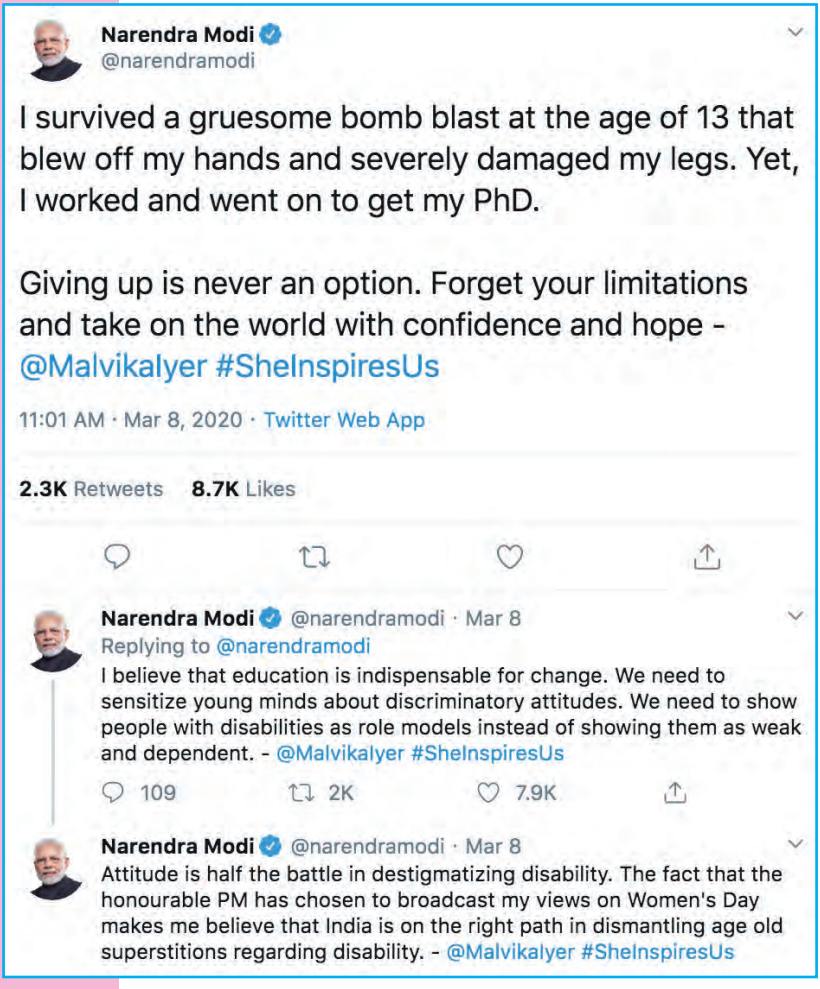

इसी प्रकार अरीफा ज़ान ने अपनी कहानी से सभी लोगों को प्रेरित किया। वे नम्दा हस्तशिल्प कला को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित हैं। विजया पवार ने बंजारा समुदाय द्वारा तैयार की जाने वाली हस्तशिल्प वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ये दोनों महिलाएं अन्य महिलाओं का भी सशक्तिकरण कर रही हैं।

कल्पना रमेश ने अपने जल जागरूकता से देश को प्रेरणा दी और पानी बचाने के लिए व्यावहारिक तरीके सुझाए।

स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कलावती देवी के प्रेरणादायी प्रयासों से बहुत लोग प्रभावित हुए। खेती करने में वीणा देवी की सफलता और अपने गांव को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता यह दिखाती है कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विद्यमान होती है। जिन लोगों ने भी #SheInspiresUs के ट्वीट या पोस्ट पढ़े वे अत्यंत प्रभावित हुए।

दिन के महत्वपूर्ण पल

जब प्रेरणादायी महिलाएं ट्वीट कर रही थी तो इस दौरान कई महत्वपूर्ण पल आए।

फॉलोअर की संख्या तेजी से बढ़ी।

प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट संचालित करने के दौरान स्नेहा मोहनदास के ट्वीटर अकाउंट के फॉलोअर की संख्या में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई।

इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विशाल संपर्क का उपयोग करके स्नेहा के अच्छे कार्य को समर्थन प्रदान किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी का ट्वीटर पासवर्ड सबकी जानकारी में

एक नागरिक ने पूछा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का ट्वीटर पासवर्ड क्या है।

और, स्नेहा मोहनदॉस के उत्तर ने सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

निश्चित तौर पर, कई लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के अकाउंट तथा पासवर्ड 'न्यू इंडिया' का इस्तेमाल करते हुए ट्वीटर में लॉगिन करने की कोशिश भी की होगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी से फॉलो बैक कैसे प्राप्त करें?

एक कुशल ट्वीटर यूजर ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से फॉलो बैक प्राप्त करने के लिए सही समय के बारे में बात की, जिसके बारे में हजारों लोगों को जानने की उत्सुकता होगी।

उन्होंने डॉ. मालविका, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अकाउंट चला रही थीं, से उन्हें फॉलो करने को कहा और मालविका ने उनका अनुरोध मान लिया।

इसे देख कर अन्य लोगों ने भी दिलचस्प चुटकुले भेजे

#SheInspiresUs के बारे में चारों ओर सकारात्मकता

लोगों ने इसके सभी क्षण का आनंद उठाया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सर्वाधिक उल्लेखनीय हिस्सा

#SheInspiresUs

देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि की ऐसी महिलाओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हैंडल के माध्यम से समूचे राष्ट्र को प्रेरित किया जो जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं इस अनूठी पहल का हिस्सा थीं।

चाहे वह स्वच्छता हो या जल संरक्षण अथवा दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता या महिलाओं के लिए कृषि हो, न केवल महिलाओं, बल्कि समूचे राष्ट्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों को इस दौरान छुआ गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF
INFORMATION AND BROADCASTING